विपक्ष और किसानों के दबाव में आकर सरकार झुकी: दीपेंद्र हुड्डा

करनाल (म.मो.)। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि विपक्ष और किसानों के दबाव में आकर हरियाणा सरकार ने धान की खरीद 3 अक्टूबर से चालू कर दी है। उन्होंने कहा कि अभी तो पूर्व सीएम मैदान में नही उतरे थे सरकार पहले ही डर गई। उन्होंने कहा कि किसानों की बदहाली और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के लिये केंद्र सरकार दोषी है। किसान भी रामलीला मैदान में धरना देना चाहते थे। लेकिन सरकार ने बॉर्डर पर रोक दिया। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को एसबीएस स्कूल रेलवे रोड पर सुबह 10 बजे से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम होगा। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में आम आदमी और पार्टी वर्कर के मन की बात सुनी जायेगी। वह आज करनाल के पीडब्लूडी रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने इससे पहले करनाल में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर वर्कर मीटिंग ली। उन्होंने आज घरौंडा और करनाल अनाज मंडियों का दौरा किया।

वहां किसानों से मुलाकात कर धान खरीद शुरु न होने पर नाराजगी व्यक्त की। इस अवसर पर किसान विक्रम ने कहा कि उसकी जीरी चार दिन से खरीद का इंतजार कर रही है। जीरी का चाबल बन गया। इसी तरह मंडी प्रधान रजनीश चौधरी ने भी जानकारी दी। इस अबसर पर पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने चंडीगढ़ में एकत्रित हो कर विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में सभी जिलों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री के विधान सभा क्षेत्र करनाल से 10 अक्टूबर को होगी। इस अवसर पर हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस संगठन की बात वह उचित मंच पर उठाते है। सरकार के किसान विरोधी रवैये के खिलाफ सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मंडियों में धान की ढेरी पर सांकेतिक धरना दिया और सरकार से धान खरीद तुरंत शुरु करने की मांग की। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार सड़क पर किसान को और मंडियों में उसके धान को पीट रही है, एक के बाद एक आर्थिक वार और शारीरिक वार कर रही है। सरकार पहले बाजरे की खरीद से पीछे हटी, अब धान की खरीद से पीछे हटती दिख रही है। किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में आ चुका है। मंडियां अनाज से अटी पड़ी हैं। उन्होंने एलान किया कि विपक्ष प्रदेश भर की मंडियों में जाकर सरकार को खरीद के लिये मजबूर करने का काम

करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर हफ्ते अपनी बात से पीछे हटने का काम कर रही है। सरकार बाजरे की खरीद तथा धान खरीद में भी पीछे हटते हुए टाल-मटोल कर रही है, ताकि कम से कम खरीदना पड़े। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकारी खरीद से पीछे हटकर तीन कानूनों के माध्यम से खरीद प्रणाली को बड़े औद्योगिक घरानों के हवाले सौंपने की जो रूप रेखा सरकार लेकर आयी है उसकी आशंका पहले ही हमने जताई थी और आज वो सही साबित हो रही है।

दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंडी में किसानों ने उन्हें बताया कि सरकारी खरीद न होने से उन्हें एमएसपी से कम पर औने-पौने भाव में अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार के उस दावे पर तंज कसा कि जो ये कहते थे कि एमएसपी थी, है और रहेगी उसकी असलियत आज सबके सामने है

सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार के घमंड, राजहठ की वजह से पिछले 10 महीनों से ज्यादा समय से किसान सडकों पर हैं, गतिरोध बना हुआ है। तीन कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन में भी किसान की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार किसानों को कुछ मान ही नहीं रही है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार किसान के खून पसीने की मेहनत के साथ मजाक नहीं कर रही। एक तरफ प्रदेश में जलभराव से किसान को काफी नुकसान हुआ। हमने मांग करी थी कि स्पेशल गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। न तो स्पेशल गिरदावरी करायी गयी न तो किसान को कोई मुआवजा मिला

10 तारीख को मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से शुरु होने वाले 'विपक्ष आपके समक्ष' कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में दीपेंद्र हुड्डा ने करनाल में वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज जनता इस सरकार से त्रस्त है। हरियाणा प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसान और मजदूर कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। साढे 7 साल की केंद्र सरकार और 7 साल की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हरियाणा को पटरी से उतारने का काम हुआ है। अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी, कानून-व्यवस्था पटरी से उतरी, किसान, कर्मचारी आंदोलित हैं, मंदी की वजह से छोटा व्यापारी तो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से गरीब आदमी त्रस्त है।

इस दौरान हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा, विधायक मेवा सिंह, विधायक बलबीर वाल्मिकी, पूर्व विधायक सुल्तान जदोला, जिले राम शर्मा , पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान, पूर्व विधायक भीमसेन मेहता, त्रिलोचन सिंह अनिल राणा, अशोक खुराना रघुबीर सिंधु, कृष्ण बसताड़ा,हरीराम साभा,कमल मान बोनी मान,रणपाल सन्धु,धर्मपाल कौशिक, सतपाल सरपंच, राजेश वैद्य,रामेश्वर वाल्मीकि,गगन मेहता,लाडी सरपंच अमरजीत धीमान सहित अनेकों स्थानीय वरिष्ठ नेता कार्यकर्त्ता मौजूद रहे।

आयोग को नही है कोर्ट की तरह तारीख लगाने का अधिकार

सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि सूचना आयोग को कोर्ट न समझें। एक केस की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए साफ किया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सिर्फ 30 दिन में सूचना देने का नियम है न कि डेट पर डेट लगाकर सुनवाई करने का।

ये आदेश न्यायमूर्ति श्री सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति शशि कांत की बेंच ने याची मुकुल की रिट याचिका संख्या 7222 वर्ष 2018 में दिया।

सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी लोग आयोग में अपील दाखिल करते समय इस आदेश की प्रति संलग्न जरूर करें और आयोग को निर्देशित करे कि आयोग इस आदेश का पालन करते हुए 30 दिन में सूचना दिलवाए न कि तारीख पर तारीख लगाए ऐसा न करने पर आयोग के खिलाफ माननीय न्यायालय में इस आदेश का पालन करने के लिए अपील जरूर दाखिल करें, क्योंकि न्यायालय अपने आदेश से बाध्य होता है और तद्नुसार कार्रवाई करने के लिए भी।

धान की सरकारी खरीद न होने से परेशान किसान करते रहे हंगामा

करनाल (म.मो.)। सरकार द्वारा धान की सरकारी खरीद 3 अक्तूबर से करने की घोषणा के बाद आज धान की सरकारी खरीद पर्याप्त न होने के कारण किसानों ने जमकर बबाल काटा। जिला भर में किसानों ने अनाज मण्डियों में सरकार की खरीद व्यवस्था के खिलाफ खूब हाय तोबा मचाई।

अधिकारियों ने नाममात्र की धान खरीद कराकर अपना पीछा छुड़वाने का काम किया। धान खरीद न होने से खफा किसानों ने जुंडला अनाज मंडी में जाने से रोकने को सडक के बीच ट्राली खड़ी कर जाम लगा दिया। जाम लगने से लोगों को आने-जाने के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। डीसी निशांत यादव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया।

आप को बता दे कि अधिकारियों ने किसानों को जुंडाला अनाज मंडी में जाने से रोकने के लिए तीनों गेटों पर ताला लगा दिया। ऐसे में किसानों की ट्रालियां सड़क के बीच में रहने से जाम की स्थिति बन गई। पहले तो किसानों ने ताला खुलवाने की गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो सड़क के बीच ट्राली खड़ी कर रास्ता जाम कर दिया। इससे करनाल से असंध मार्ग पर जुंडला में यातायात बाधित हो गया। लोगों को दूसरे रास्तों से अपने गंतव्य पर जाना पड़ रहा है। सुबह से किसान परेशान है।

धान से भरी किसानों की ट्रॉलियों को अनाज मंडी में प्रवेश तक नहीं करने दिया गया। जो अंदर दाखिल हुईं, उन्हें कच्ची प्रति देकर भेजा गया। गेट पास न काटे जाने पर किसानों में काफी रोष था। रोषजदा किसानों ने हंगामा किया। किसानों के रोष को देखते हुए मार्केट कमेटी प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एक घंटा बीतने के बाद भी किसानों का समाधान नहीं हुआ। मंडी के गेट पर ट्रॉलियों की लंबी लाइनें लग गईं।

किसानों का कहना है कि जब सरकार ने 3 सितंबर से गेहूं खरीद की घोषणा की गई है तो उन्हें गेट पास क्यों नहीं दिया जा रहा। कच्ची पर्ची से उनकी धान को प्राइवेट में खरीदा जाएगा। ऐसे में किसान को काफी नुकसान होगा। किसानों ने प्रशासन व पुलिस से गेट पास कटवाने की गुहार लगाई।

करनाल अनाज मण्डी में धान की खरीद से गुस्साएं किसानों के प्रदर्शन के बाद डीसी निशांत यादव ने करनाल मंडी में पहुंचे और कहा कि जिले में 15 जगहों पर खरीद की जा रही है। लगातार बरसात के कारण धान में 21 प्रतिशत से ज्यादा नमी है, जबकि 17 प्रतिशत तक नमी वाली धान की खरीद कर सकते हैं। बिना शेड्यूल के धान लेकर पहुंचे किसानों को दिक्कत आई जिसे हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज 15 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हो जाएगी। सरकार के माप दंड तो मानने पड़ेंगे।

मण्डी में आए किसानों का कहना है कि वह पिछले कई दिन से धान लेकर अनाज मंडी में हैं। पीछे का सारा काम खराब है। नहाना तो दूर खाना भी ठीक से नहीं हो रहा है। डीसी जो कहते है कहा कि 15 हजार मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। अधिकारियों के रवैये को देखते हुए यह सम्भव नजर नहीं आ रहा है। इस सरकार में किसानों को परेशान करने की अलावा कुछ नहीं होता।

बिना मैसेज के धान लाने वाले किसानों का कहना है कि धान की फसल 1 दिन बाद खराब हो जाती है। ऐसे में धान की फसल को कटाई के बाद खेत में रोककर नहीं रखा जा सकता। सरकार को धान की फसल पर ऐसी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। एक किसान का तर्क है कि उसके पास 10 एकड़ जमीन है। धान की फसल को कटवाने के लिए कंबाइन बुलाई मैसेज एक ट्राली का ही आएगा। बाकी फसल का वह क्या करेगा।

मार्केट कमेटी अधिकारी का कहना है कि सरकार के निर्देश की पालना करना पड़ेगा। जो सरकारी निर्देश होगे उनको नजरअदांज वह कैसे कर सकते है।